

पिघलता हिमालय

वर्ष 39 अंक 46 हल्द्वानी सम्बत् 2081 सोमवार 22 अप्रैल 2024 एक प्रति 5 रु., वार्षिक-200 रु. आजीवन 2000 रु.

संस्थापक- स्व.आनन्द बल्लभ उप्रेती
स्व.दुर्गा सिंह मर्तोल्या,
स्व.श्रीमती कमला उप्रेती

editorpighaltahimalay@gmail.com
Website-
www.pighaltahimalay.com

सम्पादक : श्रीमती गीता उप्रेती
संरक्षक : फली सिंह दत्तल
मंगल सिंह मर्तोल्या

मतदाता
रहे मौन,
पार्टियों
के
अपने
दावे

अब मतगणना तक होंगे चर्चे

लोकसभा चुनाव के लिये देशभर में मुख्य मुकाबला भाजपा और इण्डिया गठबन्धन के बीच है। इसकी शुरुआत प्रथम चरण के मतदान के साथ हो चुकी है। उत्तराखण्ड सहित 21 राज्यों में मतदान के साथ ही यह बात

भी
दिखाई
दी है
कि
देश
बदल
रहा
है।

उत्तराखण्ड की हुकूमत से रुक पाएगा पलायन?

डॉ. हरीश चन्द्र अम्डोला

1994 से ही उत्तराखण्ड को अलग राज्य बनाने की मांग होती रही जिसके लिए लम्बी राजनीतिक लड़ाई भी चली और कई लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां भी दी थीं। उत्तराखण्ड ने विकास के कई मुकाम छुए हैं। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब तक की सरकारें ठोस कदम नहीं उठा पाई हैं। 24 साल में अब तक 10 साल भाजपा और 10 साल कांग्रेस को मिले। दोनों सरकारों को उत्तराखण्ड में विकास करने का पूरा मौका जनता ने दिया लेकिन उत्तराखण्डियत का सपना कितना सच हो पाया।

स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को लेकर राज्य की जनता आए दिन सड़कों पर रहती है। पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से उत्तराखण्ड में योजनाओं को लागू करने में कई तरह की समस्याएं भी आती हैं लेकिन जब भी सरकार की इच्छा शक्ति हुई तो योजना ने परवान चढ़ी, लेकिन जब भी राज्य सरकार वोटबैंक और अपने राजनीतिक लाभ के लिए विकास कार्यों को टालती रही तो इसका नुकसान भी जनता को उठाना पड़ा है। आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। राज्य सरकारें पलायन को लेकर कोम्र ठोस नीति नहीं बना पाईं। पलायन आयोग तो बना दिया गया लेकिन इसकी रिपोर्ट को किसी भी सरकार ने गम्भीरता से नहीं लिया।

पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखण्ड को 664 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसमें से 80 प्रतिशत से अधिक आबादी पर्वतीय जिलों में हैं। वर्ष 2001 और 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक राज्य के ज्यादातर पर्वतीय जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर बेहद कम रही है। इस दौरान अल्मोड़ा और पैड़ी जिले की आबादी में 17,868 व्यक्तियों की सीधी कमी दर्ज की गई है। साफ है कि उत्तराखण्ड में पलायन आज भी बड़ी समस्या है। जिसको लेकर कोई भी सरकार गम्भीर नजर नहीं आता है। पलायन वह किस्सा है जो उत्तराखण्ड में सबसे ज्यादा सुना और कहा जाता है। हर राजनेता और सामाजिक चिन्तक भी पलायन को लेकर अपनी-अपनी चिन्ता व्यक्त करते रहते हैं। राजनीतिक दल हर चुनाव में पलायन रोकने के लिए ठोस योजनाएं बनाने के दावे करते हैं। जबकि गैर सरकारी संगठन इसके लिए सेमिनार के आयोजन कर अपना परीना बहाते हैं। इस पूरी कवायद का लाभ राज्य को कितना मिला यह तो कहा नहीं जा सकता लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी राज्य से प्रत्येक दिन 230 लोग पलायन कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पलायन पर चिन्ता केवल नारों-वादों और कागजातों में ही हो रही है जबकि हकीकत बिल्कुल विपरीत है। प्रदेश के सभी 13 जिलों से बाहर जाने वाले लोगों के आंकड़े प्रतिशत में दिए गए हैं। जिसके अनुसार नजदीकी कस्बों से 35 प्रतिशत लोगों ने पलायन किया है तो वहीं जिला मुख्यालय से 18 प्रतिशत लोगों ने पलायन किया है। इसी तरह राज्य के अन्य जनपदों से पलायन का आंकड़ा 24 प्रतिशत रहा है। राज्य से पलायन करने वाले लोगों का आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है।

यह बात तब ज्यादा गम्भीर हो जाती है जब 2018 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार प्रवासियों के रिवर्स पलायन के लिए तमाम तरह की घोषणाएं और दावे किए थे लेकिन पलायन आयोग के आंकड़ों में 22 फीसदी लोग इन चार वर्षों में राज्य के बाहर पलायन कर गए जो कि सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाने के लिए

शेष पृष्ठ 2 पर

कार्यालय प्रतिनिधि

उत्तराखण्ड की जनता मतदान तक चुप रही और अब चर्चे शुरू हो चुके हैं। प्रदेश में 8243423 कुल मतदाता हैं। इसमें से 4270597 पुरुष, 3972540 महिला व 286 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। कितने मत किस ओर पड़े यह तो मतगणना का पिटाटा खुलने पर ही पता चल पायेगा लेकिन चुनाव पर्व की फिरकी लेने वाले चूक नहीं रहे हैं और हार-जीत को लेकर दांव भी लगाये जाने लगे हैं। पूरे चुनाव

प्रचार से लेकर मतदान तक देखा गया कि प्रदेश में मुख्य लड़ाई भाजपा-कांग्रेस रही। विपक्ष की ओर से अन्य भी दावेदारी में रहे हैं लेकिन चुनाव का गणित कितना बना और कितना बिखरा यह सब जल्द पता चल जाएगा।

इस पर्वतीय प्रदेश में मतदाताओं को साधने और यहाँ से देश के अन्य राज्यों को सन्देश देने के लिये स्तर प्रचारकों में मोदी, प्रियंका, राजनाथ, योगी सहित

कई आए। इनकी सभाओं में भीड़ जुटाने के लिये पार्टी स्तर पर तैयारियों के साथ प्रचार-प्रसार का प्रसाद वितरण हुआ लेकिन मत के लिये टोली बनाकर प्रचार करने वालों की कमी थी। इससे पता चलता है कि देश बदल रहा है। जिस प्रकार नेतृगण मतदाताओं को एक दिन के लिये उपयोगी मान बैठे हैं, उसी प्रकार मतदाता भी चुपकी साधने में भलाई समझ रहा है। मौके के साथ पलट्टी खाने को तैयारी चारों ओर साफ दिख रही है।

उत्तराखण्डियों के मुद्दों पर मंथन के लिये अगले माह होगा सम्मेलन

देहरादून। विदेश मंत्रालय के सहयोग से मई में विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखण्डियों के मुद्दों को लेकर राज्य आउटरीच सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में पासपोर्ट, वीजा, आपातकालीन स्थिति में किसी प्रकार की समस्या समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक की।

उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय के सम्पर्क सीरीज के तहत उत्तराखण्ड में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिसमें प्रवासी उत्तराखण्डियों की समस्याओं के साथ ही विदेशों में शिक्षा के लिए जाने वाले राज्य के युवाओं की समस्याओं पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के अधि कारियों को निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय

की ओर से छात्र-छात्राओं को जारी की जाने वाली अंक तालिका में प्राप्त अंकों के साथ ही सीजीपीए भी अंकित किया जाए। जिससे विदेशों में उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के समय विद्यार्थियों को कोई समस्या न हो। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को केन्द्र सरकार के स्तर पर दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव व प्रस्ताव भी सम्मेलन में रखा जाए।

पिघलता हिमालय

हालातों पर छोड़ना ठीक नहीं

लोकसभा चुनाव के लिये देशभर में प्रक्रिया जारी है और प्रथम चरण में मतदान के बाद की चर्चाएँ शुरू हो चुकी हैं। अब परिणाम चाहे जो भी हो, यह सबके समझ आने लगा है कि खामखाँ भिड़ना समस्या का समाधान नहीं है। शायद यही कारण है कि महत्वाकांक्षी नेता अपने रास्ते बनाने के लिये समझौता करने लगे हैं और कारोबार को दो-चार कर आगे बढ़ाने वाले अपने रास्ते मजबूत करने लगे हैं। इनके अलावा फाइलों पर हस्ताक्षर करवाने वाले दलाल अपनी सच-झूठ की चादर पूरी बिछा चुके हैं।

चुनाव प्रचार के लिये अब पहले जैसा उत्साह किसी में नहीं है। पूरा चुनाव सोशल मीडिया पर छोड़ा गया और पार्टियों से बस्ता लेकर बूथ पर बैठने वाले रश्म निभा रहे हैं। बिल्ले-पत्तों-झण्डे लेने के लिये मचने वाली होड़ भी नहीं दिखाई दे रही है। यही कारण है कि सिर्फ सभा स्थलों पर झण्डे बैनरों की बाढ़ दिखाई देती रही है। घर-घर घूमकर बोट मांगने वालों ने भी नेता जी के रोड शो में शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी।

चुनाव आयोग की सख्ती भी एक कारण है कि तय वाहनों से ही प्रचार होना है, प्रचार सामग्री भी तय बजट में हो, अन्य तैयारियाँ भी सीमारेखा में हो और इन सबका हिसाब भी देना है। चुनाव आयोग की यह सख्ती जरूरी भी है अन्यथा लोभ-लालच के लिये कई तरह के उपक्रम अपनाए जा सकते हैं। पकड़ या शिकायत की डर से अनावश्यक खर्चों पर रोक लगी है।

इतना सब होने पर भी चुनाव लड़ना सरल नहीं रह गया है। इसमें अथाह रुपया खर्च होता है। जब प्रचार करने वालों में उत्साह नहीं है, चुनाव आयोग की ओर से भी खर्च का ब्यौरा मांगा जा रहा है, आखिर खर्च कहाँ और क्यों होता होगा? बदलते और तेज गति के समय में चमक-दमक का जोर है। तत्काल परिणाम को उतावले लोग तैस में आकर निर्णय लेने लगे हैं। इन्हीं सब उतावले लोगों को बस में करने के लिये खर्चने वाले सफल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लम्बे समय के लिये यह सब झूठा साबित होने वाला खेल है। इसलिये जन को तंत्र बनाए रखने के लिये हम-हमेशा सतर्क रहना होगा। विश्व के हालात बदल चुके हैं। ऐसे में चुनाव को इन नेताओं के हालातों पर छोड़ना ठीक नहीं। इसका परिणाम जनता को ही भुगतना होता है।



फसक

दाज्यू, मतदान के बाद खेल खतम पैसा हजम ठैरा पगल्योट में उलझाकर अपना मामला सीधा कर लेते हैं बल

दाज्यू, लोकसभा चुनाव के लिए बोट डालने के बाद खिमदा गाँव चले गये हैं। कह रहे थे- 'बोटवाजी के बाद कौन जाता है? हमने तो बंजर हो रहे मकान जमीन ठीक करनी है।' दाज्यू, खिमदा जैसे गिनती भर के लोग अपने आप से जो कुछ कर पा रहे हैं, बहुत है। आप जानने ही वाले हुए, मतदान के बाद खेल खतम पैसा हजम ठैरा। कोई पूछने-गछने वाला नहीं हुआ। सरकार बनाने वाले बनाते रहें, निचोड़ने के लिये पब्लिक ठैरी ही। दाज्यू, चुनाव के पगल्योट में उलझाकर अपना मामला सीधा कर लेते हैं बल। चुनाव लड़ रहा गोपी पार्टी टिकट तो ले आया था लेकिन हाल बुरा ही है। जनता भी हैरान है, कभी न दिखने वाले गोपी के होटल-रिजॉर्ट का काम कर रहे हैं बल। उसे क्या चाहिये पार्टी, क्या चाहिये वोट, क्या चाहिये लोक-परलोक। चल रहे सट्टे ही उसका इमान हुआ। ऐसे में किसको

क्या समझाए? अभी देशभर में प्रक्रिया चल रही है। मोदी ज्यू कह रहे हैं- '370 हटने के दर्द में टुकड़े-टुकड़े गैंग को भाषा कांग्रेस बोलने लगी है।' दूसरी ओर राहुल बरस रहे हैं- 'जुलतेबाजी से देश का मजाक बनाया जा रहा है।'

दाज्यू, नानकमता में बाबा तरसेम की गोली मारकर हत्या करने वाला शूटर अमरजीत अन्ततः मुठभेड़ में मारा गया। अमरजीत को लेकर कई बातें चल रही हैं। उसका खालिस्तानी आर्तकियों से भी कनेक्शन था बल। पुलिस वाले साब कह रहे हैं- 'हत्याकाण्ड के पीछे बड़े लोगों का हाथ है।' दाज्यू, दुनिया में कितने तरह के तुफान चल रहे हैं समझना बहुत कठिन है। कबीर, रहीम की वाणी पर कौन अमल करेगा?

चम्पावत में चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित होने पर पता चला कि मास्साब एक साल से गायब हैं। ऐसे में निलम्बन

की कार्रवाई हुई। दाज्यू, चूल्हा-चरखा की कहानी भी अजब है। एसएसजे विश्वविद्यालय में बीएससी की छात्रा को 600 में से 684 नम्बर मिले हैं बल। उच्चशिक्षा के मामले में क्या कहा जाए? वैसे भी इस विश्वविद्यालय के बनने के साथ ही कथा-कहानी बहुत हो चुकी है। परीक्षाफल समय से घोषित करने का पुरस्कार भी मिल चुका है। दाज्यू, अब तो सच-झूठ सब बराबर लगने लगा है। बागेश्वर में छेड़खानी का आरोपी प्राध्यापक दोषमुक्त करार दिया है। कालेज पढ़ने वाली बालिका की माता जी ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि असाइनमेंट जमा करने कई बालिका से प्राध्यापक ने छेड़खानी की है।

दाज्यू, अब जून का इन्तजार है। चुनाव परिणाम आने के बाद अपना बन्बू ठेकेदारी करने वाला है।

-तुम्हारा भुली झकरुवा

देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

धर्मान्तरण को लेकर मौलबी को हटाया

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने कथित जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर एफआईआर दर्ज होने के कुछ दिनों में हजरतबल दरगाह के मौलबी को पद से हटा दिया है और उनकी भूमिका की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।

भारत के साथ पनडुब्बियां बनाएगा जर्मनी

भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा कि जर्मन सरकार छह नई पारम्परिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिये भारतीय नौसेना के साथ बातचीत कर रही है, जिसमें जर्मन फ्रैम थिसेनकूप मरीन सिस्टम ऐं के रूप में भारतीय मझगांव डॉकवार्ड्स लिमिटेड के साथ साझेदारी कर रही है।

आतंकी रमनदीप की सम्पत्तियां जब्त

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने खालिस्तान समर्थक गैंगस्टर-आतंकवादी गठजोड़ से जुड़े अपराधिकार्यों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में एनआईए ने घोषित आतंकी रमनदीप सिंह उर्फ रमन की पंजाब के फिरोजपुर जिले में तिब्बती कला इलाके के झोक नोथ सिंह गाँव सहित अन्य जगह से अचल सम्पत्तियां जब्त की।

पाकिस्तान खतरनाक यात्रा देशों की सूची में

इस्लामाबाद। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमण्डल और विकास कार्यालय ने पाकिस्तान को यात्रा के लिये बहुत खतरनाक देशों की सूची में डाला है। एफसीडीओ ने ब्रिटेन नागरिकों को एडवाइज़री जारी कर तुफान, महामारी, भुखमरी और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जाने से मना किया है।

चीन का दावा- सकारात्मक प्रति हुई है

बीजिंग। चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने बड़ी सकारात्मक प्रगति की है। पिछले कुछ दिनों में यह दूसरी बार है जब चीन ने अमेरिका पत्रिका न्यूजवीक में मोदी के साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया दी है।

भर्ती घोटाले में ३६५ करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े घोटाले में 230.6 करोड़ रुपये की अचल सम्पत्तियां जब्त की हैं। जिसमें एक फ्लैट और कुछ भूखण्ड शामिल हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में 135 करोड़ की सम्पत्ति जब्त की है।

उत्तराखण्ड की....

प्रथम पृष्ठ का शेष

काफी है। सरकारी नीतियाँ पलायन रोकने में नाकाम ही रही हैं। हालाँकि देश से बाहर भी उत्तराखण्ड के लोगों का पलायन हुआ है जिनका आँकड़ा 1 प्रतिशत है। पलायन आयोग द्वारा पलायन के कई कारणों का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि आयोग द्वारा 2011 से 18 में जो कारण बताए गए हैं यानी इन दोनों कालखण्डों में पलायन के कारण सरकार और प्रशासन के अलावा सभी लचतकों को अच्छी तरह से ज्ञात थे लेकिन इनके निवारण के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। आयोग के अनुसार रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे सड़क, बिजली, पानी और कृषि और पैदावार में कमी जिसमें वन्य जीवों का कृषि पर आतंक, परिवार और रिश्तेदारों के बेहतर जीवनशैली से प्रभावित होने जैसे कर्मोवेश यही सब कारण विगत 12 वर्षों से उत्तराखण्ड की जनता के पलायन के लिए जिम्मेदार बताए गए हैं। आँकड़ों को देखें तो 50 प्रतिशत लोगों ने आजीविका के लिए पलायन किया है तो 8-83 फीसदी लोग चिकित्सा, स्वास्थ्य की कमी के चलते पलायन को मजबूर हुए हैं। शिक्षा की कमी के चलते 15-21 और 5-44 प्रतिशत लोग कृषि की कमी यानी खेती में फसलों की कम उत्पादकता के कारण पलायन कर गए यही नहीं 5-61 प्रतिशत वे लोग हैं जिनकी खेती को जंगली जानवरों

द्वारा हानि पहुँचाई जाती रही है जिसके चलते उन्होंने पलायन का मार्ग चुना है। इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि विगत पाँच वर्षों में खेती का रकबा घटा है बावजूद इसके प्रदेश को केन्द्र सरकार से दो बार कृषि कर्मणा पुरस्कार भी मिल चुका है। साथ ही किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा करोड़ों का बजट खर्च किया जा रहा है। हैरानी इस बात की है कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद कृषि उत्पादन में भारी कमी और खेती को जंगली जानवरों से हो रही क्षति के कारण कुल 11 प्रतिशत लोगों का पलायन हुआ है जो कि अपने आप में बेहद चौंकाने वाला आँकड़ा है। 8 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने अन्य विशेष कारण से पलायन किया है। हालाँकि इन कारणों का खुलासा पलायन आयोग द्वारा नहीं किया गया है लेकिन जानकारों की मानें तो इसमें ज्यादातर सामाजिक कारण हैं जो जातिगत व्यवस्था से हो सकते हैं साथ ही किसी परिवार के एक सदस्य द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी, रोजगार आदि के मिलने से उसका परिवार भी पलायन कर रहा हो आ जाता है फिर कस्बे में और फिर नगरीय क्षेत्र में पलायन बढ़ता है। वास्तव में यह एक बेहद सोचनीय विषय है कि जिस सड़क को गाँव में पलायन रोकने का बड़ा माध्यम माना जाता है वही सड़क गाँव से पलायन का एक माध्यम बन जाती है। भले ही यह पलायन अस्थायी

या नजदीकी क्षेत्रों में ही होता हो लेकिन यह भी पलायन का एक रूप ही है। राजधानी का तमगा ओढ़े देहरादून जैसे जिले के 5 ऐसे विकासखण्डों के 239 ऐसे गाँव तोक मजरे हैं जो सड़कों से नहीं जोड़े जा सके हैं। इनमें 210 गाँव ऐसे हैं जो सड़क से 5 किमी दूर हैं और 24 ऐसे गाँव हैं जिनकी दूरी सड़क से 6 से लेकर 10 किमी तक है। यह अपने आप में ही बेहद चौंकाने वाला मामला है कि 23 वर्षों से राजधानी और विकसित जिला होने के बावजूद आज भी 210 गाँव सड़कों की सुविधा से वंचित चले आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि हर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेट पर अपनी पोस्टिंग देहरादून जिले में करवाने के लिए तमाम तरह से हथकण्डे अपनाता है। साथ ही तमाम तरह से विभागों के मुख्यालय तक इसी देहरादून में होने के बावजूद जिले के गाँवों में सबसे बुनियादी सुविधा तक नहीं दी जा सकी है जिसके चलते राज्य से पलायन होने का एक कारण सड़क सुविधा को माना जा रहा है। पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से उत्तराखण्ड में योजनाओं को लागू करने में कष्ट तरह की समस्याएँ भी आती हैं। लेकिन जब भी सरकार की इच्छा शक्ति हुई तो योजना ने परवान चढ़ी किन्तु जब भी राज्य सरकार बोटबैंक और अपने राजनीतिक लाभ के लिए विकास कार्यों को टालती रही तो इसका नुकसान भी जनता को उठाना पड़ा है। आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।

खलिया टॉप मुनस्यारी का हेड है जिसे सुरक्षित रखना होगा बलाती फार्म तथा खलिया टॉप क्षेत्र मानव हस्तक्षेप शून्य हो

मुनस्यारी। प्रसिद्ध खलिया टॉप और बलाती फार्म को सुरक्षित रखे जाने के लिये क्षेत्रवासियों ने कमर कस ली है। मल्ला जोहार विकास समिति द्वारा तमाम संगठन इसके लिये आगे आ चुके हैं। मामले को तीखा होता देख स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से बातचीत को लेकर बैठक की परन्तु कोई हल नहीं निकलने के कारण आम सहमति के लिए बुलाई गई बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का गुस्सा और अधिक बढ़ गया। बैठक में तय किया गया है कि वन विभाग, कुमाऊँ मण्डल

विकास निगम, पर्यटन विभाग, खेल विभाग इस क्षेत्र में बने अपने स्क्वार्डर की फोटो तथा माप पर एक रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार के कार्यालय में जमा करेंगे। वन विभाग तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान पेयजल स्रोतों में फैली गन्दगी पर फोटो सहित एक धरातलीय रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार कार्यालय में शीघ्र जमा करेंगे। यह भी तय किया गया कि तहसीलदार द्वारा इस क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा जाएगा। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोल्या ने कहा कि बलाती फार्म तथा खलिया टॉप क्षेत्र से भारतीय सेवा को शिफ्ट करने तथा अन्य विभागों के मानव हस्तक्षेप को कम किए जाने की मांग को लेकर बुलाई गई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। कहा चुनाव बहिष्कार को सफल बनाने के लिए जो अभियान शुरू किया गया, उसकी अनुमति के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा गया था। उसका कोई प्रतिउत्तर नहीं मिलने पर पुनः पत्र भेजा गया।

उन्होंने कहा कि बलाती फार्म तथा खालिया टॉप क्षेत्र से भारतीय सेना को शिफ्ट करने तथा इस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप शून्य करने की मांग का जब तक समाधान नहीं हो जाता है तब तक किसी भी सूत्र में चुनाव बहिष्कार का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। बैठक में जोहार क्लब के अध्यक्ष केंदर सिंह मर्तोल्या ने कहा कि हम भारतीय सेना का दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें वाटर पॉइंट में रहने के इजाजत नहीं दे सकते हैं। व्यापार संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि यह सम्बन्धनशील मुद्दा है। इस पर जिला प्रशासन को तत्काल कदम उठाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य ईश्वर सिंह कोरंगा ने कहा कि बलाती फार्म तथा खलिया टॉप क्षेत्र में लगातार भारी भूस्खलन हो रहे हैं, इसलिए क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण भी किया जाना चाहिए। उक्रांड के नेता लोक बहादुर सिंह जंगपांगी ने कहा कि मुनस्यारी के 25 ग्राम पंचायतें इस क्षेत्र से पानी पीती हैं। जल का सभी स्रोत इन्हीं इलाकों में है। इसलिए इसे बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता है। बैठक में सरमोली के ग्राम प्रधान नवीन राम, सुरिंगी के ग्राम प्रधान ललित मर्तोल्या, दरकोट के ग्राम प्रधान सावित्री पांगोती, धापा की ग्राम प्रधान इन्द्रा रिलकोटिया, क्वीरीजिमिया के ग्राम प्रधान गजेन्द्र सिंह क्वीरीयाल, सेवानिवृत्त

जिलाधिकारी ने मुख्य सचिव को एक प्रस्ताव बनाकर भेजने पर सहमति दी

सेना सहित अन्य विभागों के जिला स्तर का एक भी जिम्मेदार अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं रहने के कारण आम सहमति के लिए बुलाई गई बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का गुस्सा और अधिक बढ़ गया। बैठक में तय किया गया है कि वन विभाग, कुमाऊँ मण्डल



विकास निगम, पर्यटन विभाग, खेल विभाग इस क्षेत्र में बने अपने स्क्वार्डर की फोटो तथा माप पर एक रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार के कार्यालय में जमा करेंगे।

वन विभाग तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान पेयजल स्रोतों में फैली गन्दगी पर फोटो सहित एक धरातलीय रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार कार्यालय में शीघ्र जमा करेंगे। यह भी तय किया गया कि तहसीलदार द्वारा इस क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा जाएगा। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोल्या ने कहा कि बलाती फार्म तथा खलिया टॉप क्षेत्र से भारतीय सेवा को शिफ्ट करने तथा अन्य विभागों के मानव हस्तक्षेप को कम किए जाने की मांग को लेकर बुलाई गई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। कहा चुनाव बहिष्कार को सफल बनाने के लिए जो अभियान शुरू किया गया, उसकी अनुमति के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा गया था। उसका कोई प्रतिउत्तर नहीं मिलने पर पुनः पत्र भेजा गया।

उन्होंने कहा कि बलाती फार्म तथा खालिया टॉप क्षेत्र से भारतीय सेना को शिफ्ट करने तथा इस क्षेत्र में मानव

हस्तक्षेप शून्य करने की मांग का जब तक समाधान नहीं हो जाता है तब तक किसी भी सूत्र में चुनाव बहिष्कार का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। बैठक में जोहार क्लब के अध्यक्ष केंदर सिंह मर्तोल्या ने कहा कि हम भारतीय सेना का दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें वाटर पॉइंट में रहने के इजाजत नहीं दे सकते हैं। व्यापार संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि यह सम्बन्धनशील मुद्दा है। इस पर जिला प्रशासन को तत्काल कदम उठाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य ईश्वर सिंह कोरंगा ने कहा कि बलाती फार्म तथा खलिया टॉप क्षेत्र में लगातार भारी भूस्खलन हो रहे हैं, इसलिए क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण भी किया जाना चाहिए। उक्रांड के नेता लोक बहादुर सिंह जंगपांगी ने कहा कि मुनस्यारी के 25 ग्राम पंचायतें इस क्षेत्र से पानी पीती हैं। जल का सभी स्रोत इन्हीं इलाकों में है। इसलिए इसे बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता है। बैठक में सरमोली के ग्राम प्रधान नवीन राम, सुरिंगी के ग्राम प्रधान ललित मर्तोल्या, दरकोट के ग्राम प्रधान सावित्री पांगोती, धापा की ग्राम प्रधान इन्द्रा रिलकोटिया, क्वीरीजिमिया के ग्राम प्रधान गजेन्द्र सिंह क्वीरीयाल, सेवानिवृत्त

पुलिस निरीक्षक नित्यानन्द पन्त, होटल एसोसिएशन के पूरन चन्द्र पाण्डे, देवेन्द्र सिंह देवा, रघुनाथ सिंह रावत, थानाध्यक्ष ईसी मासीवाल, रेंज अधिकारी विजय भट्ट, एडोओ उद्यान हरकोटिया आदि थे। हिमनगरीवासियों के ऐलान के बाद बलाती जिलाधिकारी रीना जोशी ने मुख्य सचिव को एक प्रस्ताव बनाकर भेजने पर सहमति व्यक्त की। खलिया टॉप तथा बलाती फार्म में जैव विविधता का 50 सालों के भीतर हुए नुकसान को मूल्यांकन के लिए प्रदेश के प्रमुख रिसर्चर्स संघों से मूल्यांकन कराया जाएगा। दोनों क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के द्वारा अब नये निर्माण पर मामले का समाधान होने तक रोक रहेगी।

मुनस्यारी के 25 ग्राम पंचायतों द्वारा बलाती फार्म से भारतीय सेना को शिफ्ट करने सहित और बलाती फार्म तथा खलिया टॉप क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप को कम किए जाने की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की घोषणा के पत्र के बाद जिला प्रशासन ने समझौता वार्ता हेतु यह बैठक बुलाई। जिलाधिकारी रीना जोशी के अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी बिन्दुओं पर विचार कर पूरे मामले का प्रस्ताव बनाने पर बात बनी।

बनकोट से बागेश्वर में शामिल करो

गणई गंगोली। क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति ने बनकोट क्षेत्र के दस गांवों को बागेश्वर जिले में शामिल करने की मांग तेज कर दी है। समिति की ओर से इसका प्रस्ताव पास कर सूचित किया गया है। क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति के

अध्यक्ष चंचल सिंह बनकोटी की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि इस क्षेत्र को हमेशा से उपेक्षा हुई है। क्षेत्र के विकास के लिये सड़क पर उतर कर संघर्ष करना पड़ रहा है। यह पूरा इलाका विकास के लिये तरसता रहा है। बैठक में

दस गांवों को बागेश्वर जिले में शामिल करने, सप्लेश्वर पुल का निर्माण करने की मांग सम्बन्धी प्रस्ताव पास हुए। यह भी कहा कि प्रस्ताव को नहीं मानने वालों का भी बहिष्कार किया जायेगा। बैठक में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।

आईआईएम के सहयोग से काशीपुर में बनेगा पर्यटन और शिक्षा का हब

काशीपुर। पौराणिक नगरी काशीपुर को विकसित करने के लिये केडीएफ आई आईएम के विशेषज्ञों की मदद लेंगे। इसमें जानकारों की राय लेते हुए नए उद्योग स्थापित करने, पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करने

और शिक्षा का हब बनाने के लिये स्थानीय स्कूलों को प्रबन्धन को बेहतर बनाया जाएगा। इससे काशीपुर राज्य के अग्रणी शहरों में अपने आप को स्थापित कर सकेंगे।

केडीएफ के अध्यक्ष राजीव घई के

नेतृत्व में आईआईएम के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में घई ने बताया कि काशीपुर को हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाना है। बैठक के दौरान मंथन में आईआईएम के निदेशक कुलभूषण बलूनी, प्रो.विवेक राय, डॉ.धीरज, स्थानीय उद्योगपति थे।

यात्री करेंगे मानसखंड कॉरिडोर के दर्शन

पिथौरागढ़। कुमाऊँ मण्डल विकास निगम और उत्तराखण्ड पर्यटन बोर्ड 500 यात्रियों को मानसखण्ड कॉरिडोर के दर्शन करवाएगा। इसके लिये स्पेशल ट्रेन संचालित हो रही है। 25 अप्रैल को टनकपुर से पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। डीएम रीना जोशी ने बताया कि दो यात्री दलों में 250-250 यात्री होंगे।

हेली से आदि कैलास यात्रा विरोध

धारचूला। व्यास घाटी से सात ग्रामों के ग्रामीणों ने हेली से आदि कैलास यात्रा का विरोध किया है। उनका कहना है कि माइग्रेसन से पहले ही बिना मन्दिर के कपाट खुले यात्रा शुरू कर दी गई है जो धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। व्यास जनजाति संघर्ष समिति के बैनर तले मिलनधर में राजन नबियाल की अध्यक्षता में बैठक में कहा गया कि हेले यात्रा के दुष्परिणाम होंगे। इससे स्थानीय रोजगार भी प्रभावित होगा।



वित्तीय अनियमितता

कार्रवाई के निर्देश नैनीताल। हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से की गई वित्तीय अनियमितता के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कुमाऊँ कमिश्नर को वित्तीय परामर्शदाता की रिपोर्ट के आधार पर जाँच कर चार सप्ताह में जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

गाँव में लगा

शराबबन्दी का बोर्ड

गैरसैंण। फण्ण गाँव में महिला मंगल दल ने पूर्ण शराबबन्दी के निर्णय के बाद गाँव की प्रवेश सीमा पर चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं। दल की संरक्षक अंजना रावत ने बताया कि शराब से बढ़ रही बर्बादी को देखते हुए महिलाओं ने यह निर्णय लिया है कि इलाके में शराब पूरी तरह बन्दी रहेगी। इसके लिये पुलिस से भी सहयोग मांगा गया है।

१० मई को खलेंगे गंगोत्री के कपाट

उत्तरकाशी। गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को अक्षय तृतीया पर्व पर सर्वाधिक अमृत सिद्ध योग व अश्विनी मुहूर्त में दोपहर 12.25 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोलें जाएंगे। मन्दिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने बताया कि इस बार जंगला से गंगोत्री तक मां गंगा की रथ यात्रा निकाली जायेगी।

चुनाव मतदान तक लुड़कना-दुरकना जारी रहा

पि.हि.प्रतिनिधि

लोकसभा चुनाव में मतदान तक नेतागर्दी के अलावा लुड़कना-दुरकना जारी रहा। इस बार के चुनाव ने जनता की आँखों के सामने जितने प्रकार के कारनामे दिखाए वह सबके दिल-दीमाग पर बैठे हैं। नेताओं का फिसलना, मुकना और अपने कारोबार की चाहत में बयानबाजी, सबकुछ खुल्लम-खुल्ला।

सरकारी भवनों पर बैठक में नोटिस

आचार संहिता की धज्जियां उड़ाती रही हैं। चुनाव आयोग ने सरकारी भवन में बैठक करने पर गंगोलीहाट विधायक फकीराम टप्टा और भाजपा नेताओं को नोटिस दिया। पिथौरागढ़ में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विरेन्द्र बोहरा, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, दायित्वधारी गणेश भण्डारी, पूर्व विधायक चन्द्रा पन्त को नोटिस दिया गया।

पति-पत्नी ने बीच चुनाव पार्टी छोड़ी

रुद्रपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष रेनु गंगवार और उनके पति सुरेश गंगवार ने चुनाव बीच कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। एनडी तिवारी के समय से गंगवार परिवार कांग्रेस का खास रहा है। खटीमा में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश उपाध्यक्ष मीना सोनकर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे डाला। इससे पहले पूर्व कबीना मंत्री दिनेश अग्रवाल भी भाजपाई बने थे।

डॉ. हरीश बिष्ट का इधर-उधर जाना

भीमताल के ब्लाक प्रमुख डॉ.बिष्ट चुनाव के समय फिर से भाजपाई बन गए। डॉ. बिष्ट पहले भी पार्टी भाजपा-कांग्रेस करते रहे हैं। क्षेत्र में खासी पैठ होने के साथ ही हमेशा महत्वाकांक्षा के लिये इधर-उधर जाने पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। पलड़ा भारी देख उनके बदल जाने पर कार्यकर्ता भी सवाल करने लगे हैं।

पार्टी में आने वाले संस्कारवान बनेंगे

देहरादून। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जो भी लोग भाजपा में आए हैं, उन्हें पार्टी की रीति-नीति के दृष्टिगत संस्कारवान और क्षमतावान बनाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति में सदगुण और दुर्गुण दोनों होते हैं। हम सदगुणों को बढ़ाएंगे और दुर्गुण को खत्म करेंगे। जितने भी नेता और कार्यकर्ता अभी तक भाजपा में शामिल हुए हैं उन सभी को काम में लगाया जा रहा है।

चाचा-भतीजे मिल कर ले रहे लाभ

लोहाघाट। विधायक खुशाल अधिकारी के भतीजे आनन्द अधिकारी के भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व विधायक व भाजपा नेता पून सिंह फर्त्याल ने कहा कि चाचा-भतीजा मिलकर सत्ता का लाभ ले रहे हैं। ये इनकी सांठगांठ है जो सत्ता पक्ष का संरक्षण लेना चाहते हैं। इससे भाजपा की साख गिर रही है। विधायक खुशाल सिंह ने फर्त्याल के आरोपों को खारिज कर दिया है।

लोहाघाट में भी लुड़कते रहे

लोहाघाट। लोहाघाट में पूर्व ब्लाक प्रमुख योगेश मेहता, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भूपाल मेहता, युथ कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अमित साह, विपिन गोरखा, जमन सिंह धौनी, उमेश जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के सामने भाजपा की सदस्यता ले ली। कहा- पीएम सीएम के कार्यों से प्रसन्न होकर भाजपा में आ रहे हैं।

छात्र नेता भी मौका देखकर शामिल

हल्लदानी। एमबीपीजी कालेज की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया जो एबीवीपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव जीती थी, अब चुनाव मौके पर भाजपा में

शामिल हो गईं। एबीवीपी से नाराज रश्मि कई बार कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी दिखाई दे रही थीं। उनके साथ कुछ छात्र नेता भी भाजपा सदस्यता लेने देहरादून तक गये।

निर्दलीय उमेश का हरदा के लिये दावा

हरिद्वार। निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने सोशल मीडिया में दावा किया कि हरीश रावत 19 अप्रैल के बाद भाजपा में शामिल होंगे और उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा। यह भी लिखा कि हरीश रावत 10 विधायकों को भी भाजपा में शामिल करवाएंगे। निर्दलीय के दावे से राजनीतिक गलियारों में हड़कम्प मच गया।

स्टिंगबाज सांसद का सपना देखने लगे हैं

हरिद्वार। निर्दलीय उमेश कुमार के दावे पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कैसे बिडम्बना है कि अब स्टिंगबाज भी सांसद बनने का सपना देखने लग गए हैं। कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी को भाजपा का एजेंट करार देते हुए झूठ और साजिश की पराकाष्ठा करार दिया।

भारत विश्वगुरु बनने की राह पर

हल्लदानी। पूर्व सीएम एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दावा किया कि इस बार के चुनाव के बाद भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है। कहा पीएम मोदी की जड़ें देश की माटी से जुड़े हैं और पंडित जवाहर लाल नेहरू की जड़ें विदेशों से जुड़े थे। भगत दा ने कहा उन्होंने राजनीति छोड़ी है राष्ट्रनीति नहीं छोड़ी।

मानसिक संतुलन खो चुके भाजपाई

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन

माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताये जाने की निन्दा की। कहा कि भाजपा नेता मानसिक संतुलन खो चुके हैं।

गवैय्या बन गये बहुत सारे

चुनाव में इस बार पहले की तरह पार्टियों के गीत नहीं सुनाई दिये जो दिनभर चलते थे। लेकिन चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिये गीत-संगीत को भी माध्यम बनाया और स्वीप टीम इसमें जुटी रही। इस दौर में जब हर कोई अपनी हाजिरी लगाने में पीछे नहीं है, बहत सारे गवैय्या बन गये और मतदान करने के लिये गीत कविताएं रची गईं। कुमाऊँ कमिश्नर दीपक रावत ने भी 'सुन ओ आमा बूबू मतदान करी आला' गीत गाया, जिसको मीडिया ने खूब प्रचारित किया।

पूर्व राज्यमंत्री जया भी भाजपाई बनी

नैनीताल। 'इस रंग बदलती दुनिया में' गीत का स्मरण हो सकता है क्योंकि जिस हिसाब से नेता अदल-बदल होते हैं। 2007 में कांग्रेस पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ चुकी, पूर्व राज्यमंत्री जया बिष्ट ने भी हल्लदानी में भाजपा सम्भाग कार्यालय पहुँच कर सदस्यता ले ली। जया 1976 से कांग्रेस की सक्रिय सदस्य रही हैं और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष भी थीं। जया कहती हैं- कांग्रेस पार्टी की नीति जहाँ जन विरोधी होती जा रही है।

शकुन्तला दताल भी भाजपा में

जोलजीवी। क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाली श्रीमती शकुन्तला दताल ने भाजपा में आकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का स्वागत किया। सीएम के दौरे के समय वरिष्ठ नेता शकुन्तला ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस को छोड़ भाजपा का

झण्डा थाम लिया। इससे पहले वह कांग्रेस में बेहद सक्रिय थीं और विधायक हरीश धामी की खासी समर्थक भी रही हैं।

५०० सीटें भी आ सकती हैं : भगत

कालादूंगी। विधायक बंशीधर भगत बहुत ही उत्साहित होकर कह रहे हैं कि वर्तमान हालातों में भाजपा 500 सीटें प्राप्त कर सकती है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा के पक्ष में जितनी लहर इस समय चल रही है उतनी राम मन्दिर के समय भी नहीं चली थी।

चुनाव के बाद फिर से बुल्डोजर

रामनगर। मालधन में चुनाव प्रचार के लिये पथारे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जे के जरिये देवभूमि का स्वरूप बदलने की कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। चुनाव के बाद फिर से बुल्डोजर चलेगा। समान नागरिक संहिता के लिये यूसीसी लेकर आए हैं।

डायनासोर की तरह विलुप्त हो रही पार्टी

लोहाघाट। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा जाति पंथ व मजहब की नहीं बल्कि इन्सान और इन्सानियत की बात करती है। कहा, कांग्रेस डायनासोर की तरह तरह विलुप्त हो रही पार्टी है।

नैनीताल सीट : नेताओं पर दबाव

नैनीताल-उधमसिंह नगर लोकसभा सीट पर भाजपा के अजय भट्ट और कांग्रेस के प्रकाश जोशी की सीधी टक्कर में उन नेताओं पर दबाव रहा है जिनकी चाहत भविष्य में विधायक के लिये पार्टी टिकट की हो। इनके बोल में सुना गया कि जो मेहनत नहीं करेगा आगे भी टिकट है...

पांगू-अस्कोट-आराकोट अभियान २५ मई से ८ जुलाई

पि.हि.प्रतिनिधि

नैनीताल। इस बार अस्कोट-आराकोट अभियान 25 मई से 8 जुलाई तक चलेगा। अपने गाँव को जानो, लोगों को पहचानो, तालों-बुर्यालों के संग अपनी नदियों को समझने के अभियान को आज से 50 साल पहले 25 मई से 8 जुलाई 1974 के बीच नव स्थापित कुमाऊँ गढ़वाल विश्वविद्यालयों के छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीणों ने उत्तराखण्ड के पूर्वी काने पर नेपाल सीमा पर स्थित अस्कोट से पश्चिमी काने में हिमाचल से लगी सीमा पर आराकोट तक की अध्ययन यात्रा की थी। इस यात्रे के लिए सुन्दरलाल बहुगुणा ने उन्हें प्रेरित किया था। संग्रामी श्रीदेव

सुमन के जन्मदिन 25 मई को यात्रा शुरु हुई। यात्रा के माध्यम से पहली बार अभियान अन्य मार्गों में गया। 1975 में श्रीनगर से शिमला, 1978 में श्रीनगर तथा तथा 1977 में नैनीताल से गोपेश्वर यात्रा की गई।

दस साल बाद पहाड़ तथा सहयोगी संस्थाओं ने तय किया कि 25 मई से 8 जुलाई 1984 के बीच एक बार फिर उन्हीं तिथियों और उसी मार्ग से यात्रा कर एक दशक में हुए परिवर्तनों को समझने की कोशिश की जाय। यात्रा को और विस्तार दिया गया। पांगू से अस्कोट, वान से रमापौ, झिन्डी, पाणा, कुंवारी पास, ढाक पोतवन-रेणी, जोशीमठ होकर गोपेश्वर, घुत्तू-बूढ़ाकंदार-उत्तरकाशी अदि नए स्थान

और माई इसमें जोड़े गए। इस बार कुछ साथियों ने कोटरगढ़ से कर्णप्रयाग और अल्मोड़ से श्रीनगर की भी अध्ययन यात्रा की। 1984 से 1995 के बीच उत्तराखण्ड के भीतर तथा अन्य हिमालयी राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल) तथा देशों (नेपाल, भूटान तथा तिब्बत आदि) में यात्राएं की गईं। इसी तरह 2004 में चौथा और 2024 में पांचवा अस्कोट आराकोट अभियान आयोजित हुआ।

2014 में आयोजित पांचवा अस्कोट आराकोट अभियान स्वतंत्रता सेनानी श्रीदेव सुमन के जन्मदिवस 25 मई को पांगू से कोट्टा प्रसाद भट्ट द्वारा रवाना किया गया। उन्होंने इस यात्रा को 'जंगम विश्व

विद्यालय' नाम दिया। अमरीका, कनाडा और जर्मनी से आए शोधार्थियों, प्राध्यापकों समेत भारत के 8 राज्यों के लगभग 200 से अधिक लोगों ने अभियान में हिस्सेदारी की थी। और अब 2024 में सम्पन्न होने वाली यात्रा इस अभियान के पचासवें साल में है।

पिछले 5 दशकों में और खासकर राज्य बनने के द्वाइ दशक बाद उत्तराखण्ड का प्राकृतिक चेहरा- जल, जंगल, जमीन, खनन, बांध, सड़क आदि के बहाने कितना और घटा है? अर्थ व्यवस्था किस बिन्दु पर है? दलित और अल्पसंख्यकों की स्थिति कैसी है? पलायन का क्या रूप है? गाँव के हाल कितना बदले हैं? शिक्षा, चिकित्सा, सड़क,

पानी, शराब, विभिन्न आपदाओं तथा महिलाओं-बच्चों सहित पर्वतीय जीवन के अन्य पक्षों की क्या स्थिति है, यह सब जानने-समझने के लिये 25 मई के यह यात्रा शुरु की जा रही है। अभियान की केन्द्रीय विषयवस्तु या थीम 'स्रोत से संगम' रखे गई हैं। ताकि नदियों से समाज के रिश्ते को गहराई और समग्र जलागम के संदर्भ में समझा जा सके। साल के अन्तम महीनों में टनकपुर से डाकपथर (तराई भाबर-दून) यात्रा को अभियान के दूसरे चरण के रूप में आयोजित करने की योजना है। इस अभियान के माध्यम से लोगों को सीखने और अपने अनुभवों तथा आज की असलियत को लोगों तक पहुंचाने की दोतरफा कोशिश होगी।

‘कालयुक्त’ नाम संवत्सर २०८१ विक्रमी प्रारम्भ होने की शुभकामनाओं के साथ-

तुषार
अस्पताल
चंद फार्म
(रेलवे स्टेशन के पास)
टनकपुर

SIDDHIVINAYAK
SOLVENT LLP
Plot No. C-8A, Phase-III
ELDECO Sidcul Industrial Park
Sitarganj (US Nagar)

न तेरा न मेरा **Thats**
APNA GHAR चौकोड़ी
HOTEL RESTRO BANQUET (माँ कोटगाड़ी, नौलिंग देव, पातालभुवनेश्वर)
मो.- 9458920379, 6396098804
पितृछाया- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. जोगासिंह मर्तोल्या

YOGA
MEDITATION

LIVE
MUSIC

HOMELY
FOOD

BIRTHDAY
WEDDING

Near by-

Hotel
Bala Paradise
Tiksain, Munsiri
Ph. 05961222237, 9412951678

घर से बाहर
घर का सा
होटल

MARTOLIA
FURNITURE
A unit of Martolia Enterprises
Pilikothi, Haldwani
Mob- 8057167777, 7906752084, 8650427229

Hayat Paradise
Bus Station
Munsiri
Ph. 09411556700, 9997733070

लक्ष्य इन
मदकोट
सम्पर्क
7351285555

धमोत होम स्टे
धरमघर/चकोड़ी
(एडवेंचर जोन, ट्रेकिंग, माउंटन वाइकिंग, स्थानीय व्यंजन)
मो. 9760007148
www.mountainheights.in

माँ नन्दा आयरन एण्ड बिल्डिंग
मैटेरियल, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी
(सीमेन्ट, सरिया, टाइल, पेण्ट, सेनेटरी, हार्डवेयर)
गोदाम- जोहार एसोसिएट्स
बच्चौनगर- 1, कमलुवागांजा, हल्द्वानी
मो.- 7409440813, 7500619761

पूर्ण कालिक
संगीत प्रशिक्षण
केन्द्र
हिमालय संगीत
शोध समिति
जे.के.पुरम्, सेक्टर डी
छोटी मुखानी
हल्द्वानी
सम्पर्क- 9411563413

होटल माँ नन्दादेवी एण्ड बारातघर
नानासेम, मुनस्यारी
गणेश सिंह मर्तोल्या एण्ड सन्स
हार्डवेयर, बिल्डिंग मैटेरियल, जनरल आर्डर सप्लायर्स
फोन सम्पर्क- 05961-222236
8958525979, 9411134775

Enjoy Beauty of Himalaya at
MARTOLIA LODGE
Family Guest House- Sarmoly, Munsiyari
A Home Away From Home & Home Stay
Phone: (05961) 222287

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीमती गीता उप्रेती द्वारा पिघलता हिमालय, जे०के०पुरम्, सेक्टर डी, छोटी मुखानी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड से प्रकाशित एवं शक्ति प्रेस, जे०के०पुरम्, सेक्टर डी, छोटी मुखानी, हल्द्वानी (नैनीताल) से मुद्रित।
सम्पादक: श्रीमती गीता उप्रेती फोन/फैक्स: (05946) 264013, 9458961490, 9411770280, 9411301014,
editorpighaltahimalay@gmail.com
Website- www.pighaltahimalay.com